(d) It was anticipated that approximately Rs. 5,000 crores would be collected every year. During the 9th Plan period a sum of Rs. 551 crores has been allocated/earmarked to NHAI as Govt. of India's investment.

Extension of the Super Highway From Siliguri to Guwahati

†*124. DR. (SMT.) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any plan for construction of Super Highway connecting different regions of the country;

(b) whether there is any scheme for extending the Super Highway Scheme from Siliguri upto Guwahati and onwards;

(c) if so, in what manner; and

(d) if not, whether Government would consider the scheme for successful completion within the Ninth Five Year Plan itself?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJNATH SINGH): (a) to (c) The plan is to improve the highways connecting the four metropolitan cities of Mumbai, Delhi Chennai, Calcutta and East-West road from Silcher to Porbandar and North-South road from Kanyakumari to Srinagar to 4/6 lane facility. This includes highway from Siliguri to Guwahati and Silchar. The project will be completed in next 10 years by National Highway Authority of India.

(d) Does not arise.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, the decision to construct super highways is, definitely, a welcome decision. But it is a fact that many States are excluded, particularly, my State is excluded, from the construction of super highways. With regard to the construction of super highways, of course, it is a fact that there is a shift of traffic from railways to road. The super highway, to a certain extent, takes care of it. But, many other agencies are also involved in it. It requires trucks that can carry more tonnage of goods; fuel

† Starred Question Nos. 121 and 124 were taken together.

345/RS/F-1

stations are required; motels are required; transhipment points are required; weighbridges are required; traffic aid points are required, and many equipments are required. So, many agencies are involved in it. I would like to know as to how the National Highway Authority is co-ordinating with these many agencies. And, is there any institutional set-up for the co-ordination of all these agencies in the development of national highways?

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, नेशनल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत् नार्थ से साऊथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक कोरीडोर बनाने की योजना है और साथ ही साथ दिल्ली को, जो मेट्रो सिटीज हैं उनसे जोड़ने की एक गोल्डन क्वेड्रिलेटिरल योजना है। कोशिश यह की गई है कि अधिक से अधिक राज्य इस योजना के अंतर्गत आ जाएं, जिनसे होकर हमारी नेशनल हाइवेज की सड़कें गुजर सकें। केरल राज्य का जहां तक संबंध है, मैं यह दिखवा लूंगा कि केरल राज्य से यह हमारा कारिडोर्स अथवा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो रोड जा रही है, तो कितने किलोमीटर केरल राज्य में यह कवर होती है, इसकी मैं जानकारी कर लूंगा और माननीय सदस्य को भी अवगत करा दूंगा।

जहां तक एजेंसीज़ का सवाल है रोड्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में, हमने अब तक 20 प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिनमें से 16 प्रोजेक्ट्स के कांट्रेक्ट्स दिए जा चुके हैं, इनमें 14 हमारी इंडियन कंपनियां हैं और एक फॉरेन कंपनी है जिसको कि हमने 2 प्रोजेक्ट दिए हैं।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, the answer to the (d) part of may question regarding the amount of cess collected out of the levy on petrol and diesel so far and made available to the National Highways Authority of India is that it was anticipated that approximately Rs. 5,000 crores would be collected every year. During the Ninth Plan period, a sum of Rs. 551 crores has been allocated or earmarked to the National Highways Authority, as Government of India's investment. I think there is some confusion in this answer. If Rs. 5,000 crores is collected every year as the cess on petrol and diesel for the development of National Highways, why for the whole five-year period only Rs. 551 crores have been allocated?

श्री राजनाथ सिंह: सर, माननीय सदस्य की जो यह शंका है, इसे मैं उचित ही मानता हूं लेकिन जो यहां पर मैंने कहा है कि फंड रिक्वायरमेंट हमारी कैसे पूरी होगी, तो डीज़ल-पैट्रोल पर जो सैस लगेगा, उससे हमारी फंड रिक्सवायरमेंट पूरी होगी, एक्सटरनल फंडिंग के द्वारा हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, प्राइवेट सैक्टर पार्टिसिपेशन के द्वारा हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और टोल रिवेन्यूस के द्वारा हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह मैं बतला सकता हूं कि इन नौवीं पंचवर्षीय योजना में सैस के द्वारा, एक्सटरनल फंडिंग के

द्वारा, टोल के द्वारा कितने रिवेन्यूस का, फंड का हम कलेक्शन कर लेंगे। वैसे तो 13,000 किलोमीटर की पूरी इन सड़कों को बनाने के लिए ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्यः इस्तेमाल कितना करेंगे?

श्री राजनाथ सिंहः बतला रहा हूं, 54,000 करोड़ रुपए की हमको आवश्यकता होगी और इस 54,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कैसे होगी—सैसऑन पैट्रोल और डीज़ल के द्वारा पंचवर्षीय योजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो जाने का अनुमान है, एक्सटरनल फंडिंग के द्वारा भी 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो जाने का अनुमान है, प्राइवेट सैक्टर पार्टिसिपेशन के द्वारा भी 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था होने का अनुमान है, अब तक प्राइवेट सैक्टर पाटिसिपेशन के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, और शेष जो धनराशि बचेगी टोल रिवेन्यूस के द्वारा उसकी हम व्यवस्था करेंगे।

DR. (SMT.) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA: Will the hon. Minister kindly state whether there is any proposal for a new highway to connect Assam and the North-Eastern Region with other parts of India as, at present, there is only one railway line and one highway which connects Assam and the North-Eastern Region with other parts of India?

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन् माननीय सदस्या ने जानना चाहा है कि नॉर्थ-ईस्ट और ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर में आसाम स्टेट में कितनी किलोमीटर रोड्स आती हैं? श्रीमन् नेशनल हाईवे नंबर-54 सिल्चर टू डबोका 290 किलोमीटर, नेशनल हाईवे नंबर-36 डबोका टू नौगांव 36 किलोमीटर, नेशनल हाईवे नंबर 37 नौगांव टू दिसपुर 110 किलोमीटर और नेशनल हाईवे नंबर-31 गुवाहाटी टू नॉर्थ सलवारा 180 किलोमीटर है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Charman, Sir, while replying to the second supplementary of Shri Pillai, the hon. Minister quoted some figures, and that confusion still continues. I want to seek a clarification from the hon. Minister whether the Rs. 551 crores which has been earmarked and allocated by the Planning Commission for the five years is a budgetary support. Surely, it cannot be out of the Rs. 5,000 crores which the Government is recovering annually as a cess on petrol and diesel.This Rs. 551 crores must be the budgetary support for a period of five years which the Finance Minister is giving from his pocket. I understand, that is the position. In that context, I would like to know from the hon. Minister whether this entire amount of Rs. 5,000 crores which the Government is collecting as cess on petrol and diesel is being transferred to the National

Highways Authority or other road construction authorities and the Ministry of Shipping and Transport, or, a part of it is kept by the Finance Minister as part of the General Revenues because, that has been become a practice.

Thirdly, the hon. Minister has said, that, approximately Rs. 5,000 crores will be coming to the Government, but I would like to know precisely as to what the rate of cess which the Government is having, and on the basis of that, over a period of five years, how much you are going to have, and to what extent it is going to fund your this Particular project of North-South-East-West corridor.

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उस के संबंध में मैंने कहा कि 'सेस' के द्वारा प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपए का कलेक्शन होने की संभावना है और इस संबंध में जो आप की शंकाएं हैं, मैं समझता हूं कि जब हम 'सेस' लेकर पार्लियामेंट में आएंगे तो उन सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। श्रीमन् दूसरी चीज आप ने जो जानना चाही है, जो हम ने अपने उत्तर में भी दी है कि 551 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि बजट के द्वारा अलॉट हुई है।

श्री गया सिंह: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस के संबंध में मेरी एक शंका है जिसे मंत्री जी कृपया दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा और लगभग 54 हजार करोड़ में से 45 हजार करोड़ रुपया कलेक्ट करने का उन का अनुमान है। शेष 9-10 हजार करोड़ रुपए के बारे में वह कहते हैं कि वह टोल वगैरा से प्राप्त करेंगे, लेकिन जब तक रोड नहीं बनेगी तो टोल कहां से शुरू हो जाएगा? यह बात अभी क्लिअर नहीं हो रही है और इन्होंने 14 या 16 तारीख को ही टेंडर अलॉट किया है तो वह काम भी शुरू नहीं हुआ है। अब यह कार्य 10 साल में पूरा हो जाएगा, इस के बारे में मैं मंत्री जी से स्थिति स्पष्ट जानना चाहूंगा।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् टोल कहा से प्राप्त होगा, यह जानकारी माननीय सदस्य ने चाही है और मैं बताना चाहूंगा कि हम ने नेशनल हाइवे डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सड़कें ली हैं, उस में 504 किलोमीटर में काम 'गोल्डन क्वाड्रीलेटरल योजना' में आने वाली सड़कों को पूरा हो चुका है। साथ ही 630 किलोमीटर ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर की सड़कों का काम भी हम ने पूरा कर लिया है यानी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। तो जहां आवश्यकता है वहां हम टोल रेवेन्यू वसूलने की व्यवस्था करेंगे और उस के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, उस में हम ने अनुमान लगाया है कि वह टोल रेवेन्यू के माध्यम से हम को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that while calling for tenders for these works, some criterian has been laid down, according to which no Indian company would be able to compete in these bids, only multinational companies and companies from outside the country become eligible for bidding in these tenders. Is it a fact? If so, whether it has come to the notice of the Minister?

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् यह कहा जाना कि इंडियन कांट्रैक्टर्स को हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, यह उचित नहीं होगा। प्री-क्वालिफिकेशन का निर्णय लेते समय ऐप्लीकेशंस इनवाइट की गई थीं कांट्रैक्टर्स के द्वारा और हमने 160 ऐप्लीकेशंस रिसीव की थीं। 160 में से इंडियन कांट्रैक्टर्स की संख्या 154 थी और फॉरेन कांट्रैक्टर्स की संख्या 6 थी। इन ऐप्लीकेशंस को ऐक्जामिन करने के बाद 91 इंडियन कांट्रैक्टर्स और 6 फॉरेन कांट्रैक्टर्स को फाइनलाइज़ किया गया। जैसा मैंने पहले कहा कि हम 16 प्रोजेक्टस के काम ऐवार्ड कर चुके हैं, इन कांट्रैक्टर्स को, और इन 16 में से 14 प्रोजेक्ट्स हमने इंडियन कांट्रैक्टर्स को 2 प्रोजेक्ट्स का ऐलोकेशन किया है। इसलिए यह कहना कि इंडियन कांट्रैक्टर्स को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, my question is with regard to parts (c) and (d), in regard to the cess collected out of the sale of petrol and high speed diesel. The Finance Minister had said in this years, Budget that he had earmarked a part of this money for the Central Road Fund, but till now, a mechanism could not be evolved to give this money to you. My query is with regard to this year, 1999-2000. I would like to know whether the money supposed to be received from this cess from the Finance Ministry has been worked out by your Ministry, and whether you can assure this House that you will be in position to get this money for your Ministry for this year, even if the mechanism is not there. Would you ensure that the money is kept for you? Please give an assurance to the House and to the people who are paying the one rupee cess per litre of oil. You must give this assurance with regard to the money you are supposed to get for this year, the money you have got already, and as to how you would ensure that this money is kept for you for this year.

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् सैस बिल पार्लियामेंट द्वारा पारित हो जाने के बाद जो भी एमाउंट कलेक्ट होगा, वह सैस फंड में जाएगा लेकिन सैस के द्वारा जो कलेक्शन....**(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु: लेकिन यह तो प्रिविलेज का सवाल बनता है क्योंकि बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी का आश्वासन था देश के लिए तो यह इस साल से लागू होना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंहः महोदय, पूरा सदन जानता है कि अभी तक सैस बिल, पारित नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि सैस बिल जल्दी ही लेकर हम पार्लियामेंट में आने वाले हैं और उसके बाद जो भी कलेक्शन होगा वह सैस फंड में जाएगा और सैस के द्वारा जो कलेक्शन होगा वह 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान है। इसका 50 परसेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए जाएगा और शेष एमाउंट सेंट्रल रोड फंड में जाएगा।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I seek your protection, Sir. (*Interruptions)* Can I not get this figure in Parliament? This is in the Budget Statement. I know that there is a one rupee cess collection and the ratio. But the Ministry has not even worked out as to how much it is supposed to get for this year out of the cess fund.

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन् मैं तो ऐस्टीमेट बता रहा हूं। एक्चुअल एमाउंट कितना होगा, इसकी जानकारी तो बाद में होगी।

श्री दीपांकर मुखर्जीः एक रुपया प्रति लीटर, मैं कैलकुलेट करके दे देता हूं आपको।

श्री राजनाथ सिंहः इस समय ऐस्टीमेट कर पाना कठिन है।

श्री दीपांकर मुखर्जीः मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप सुन नहीं रहे हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं, मुझ से पुछिए।

श्री राजनाथ सिंहः इस समय ऐस्टीमेट कर पाना कठिन होगा, इसलिए कठिन होगा कि पेट्रोल और डीज़ल का कितना कंज़म्पशन होता है, इस बात पर यह निर्भर करेगा कि सैस का कलेक्शन कितना होगा।

श्री दीपांकर मुखर्जीः कंज़म्शन तो रोज का है।

SHRI V.P. DURAISAMY: Thank you very much. I would like to know whether the Transport Ministry has received any complaint from Tamil Nadu with regard to BOT scheme. In Namakkal,Tamil Nadu, for the construction of 9 Kms. of bypass road, the department has already acquired land and the money has been allocated by the Transport Ministry, Government of India.

I understand that some problems have been raised with regard to the construction of these roads under the BOT scheme. I would like to know whether the Ministry has received any such complaint. If so, what is the alternative proposal to complete these projects?

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन्, मैं समझता हूं यह प्रश्न इस ऑरिजनल प्रश्न के रिलेटिड नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है अगर सम्भव होगी तो मैं उनको दे दूंगा।

DR. M.M. DAS: Sir, the six-lane National Express Highway certainly sounds as a grand national slogan, and, if implemented, it will immensely benefit the country. But I have a question for the Minister as to what has happened to the earlier project connecting all the metropolitan cities, namely, Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. I would also like to know whether it is still under the consideration of the Government. Thirdly,Sir, there are some intensive traffic points such as Pune-Bombay where a six-lane National Highway is necessary. But what about the hundreds of kilometres of rural stretches where only one or two lanes may suffice, and why should you not divert that amount to the starving States where there is no infrastructure of highways or very inadequate infrastructure of highways?

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, गोल्डन क्वाडिलेट्रल योजना के अन्तर्गत हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उनके भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऑलरेडि 504 किलोमीटर सड़क फोर लेनिंग हो चुकी है और वैसे ही कॉरिडोर्स में भी 630 किलोमीटर यह सड़क बन चुकी है। लेकिन जिस संबंधित क्षेत्र की जानकारी माननीय सदस्य ने चाही है अगर उसकी लिखित रूप में जानकारी मुझसे चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनको दे दूंगा।

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, the hon. Minister has said that out of the 16 projects allocated, there was a foreign company which has been allocated two such projects. Is it possible to indicate the name of this company? Sir, there was a newspaper article indicating that the World Bank-aided projects would exclude the Indian companies. My hon. friend had put this question. But no answer has been given. There was a newspaper report which appeared throughout the country but it has not been refuted by the Government. So, this House would like to know whether any such conditionality exists in relation to the World Bank-aided projects.

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् जिस फॉरेन कम्पनी का नाम जानना चाहा है तो उस फॉरेन कम्पनी का नाम है—मैसर्स पी०टी० कम्बर मित्रजया (इंडोनेसिया)। इनका दूसरा प्रश्न था कि.....

श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा: जो वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजेक्ट्स हैं वह हमारे वेंकैया नायडु साहब ने बोला है, अखबारों में निकला है कि इन प्रोजेक्ट्स में इंडियन कम्पनीज को एक्सक्लूड किया जाएगा। यह न्यूज पेपर्स रिपोर्ट पूरे देश में छप चुकी है। उसका किसी ने भी डिनॉयल नहीं

दिया है गनर्वमेंट की तरफ से और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजेक्ट्स, जो सड़कों से संबंधित हैं, उसमें इंडियन कम्पनीज इंक्लूड नहीं की जाएगी।

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन् नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं कांट्रेक्टर्स के लिए, कांट्रेक्सर्ट की प्रि-क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए। यह बात सही है हमारी इंडियन कम्पनीज ऐसी बहुत कम हैं जो कि इस प्रि-क्वालिफिकेशन को पूरा कर पाती हैं। लेकिन एक रास्ता हम लोगों ने निकाला है कि हमारी जो इंडियन कम्पनीज हैं वे फॉरेन कम्पनीज के साथ जोइंट वेंचर का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जोइंट वेंचर का फॉर्मेशन करने से एक तो हमारी इंडियन कम्पनीज को एक्सपीरिएंस भी मिलता है और कुछ असेट्स भी उनके पास आ जाती है तथा उनकी फाइनेंसियल कंडीशन भी इम्प्रूव कर जाती है। हम तो चाहते हैं कि हमारी इंडियन कम्पनीज की भी एफिसिएंसी बढ़े इसलिए जोइंट वेंचर की इजाजत हमारी मिनिस्ट्री ने दे रखी है।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, unfortunately, this North-South corridor cannot be extended beyond Madras. The Southern most point of this country is Kanyakumari. I would like to give a suggestion to the hon. Minister. The suggestion is, there should be a Western corridor for Kanyakumari to Mumbai connecting the ports like Cochi, Mangalapuram and Goa. So, I would like to know from the hon. Minister whether he would consider this proposal.

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन्, माननीय सदस्य का जो सुझाव प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से उस पर मैं विचार करूंगा।

Chartering of Aircrafts by AI for Carrying Haj Pilgrims

*122. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the number of aircrafts which were chartered by Air India for operating Haj flights during the last three years;

(b) the details of the chartering cost of each aircraft and number of passengers carried; and

(c) whether it has come to the notice of Government that Air India is paying higher fare on chartering and the aircrafts are not certified as airworthy?